वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण

*442. **प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा:** क्या वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं से कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया है और इस ऋण पर कितनी ब्याज दर देय है;

(ख) क्या सरकार ने इन वित्तीय संस्थाओं का ऋण चुकाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) सरकार बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गम करती है, जिसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा अभिदान किया जाता है। इन प्रतिभूतियों में अन्तर्निहित ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं क्योंकि इन्हें अलग-अलग समय पर जारी किया जाता है।

(ख) और (ग) सरकार ने वर्ष 2003-04 के बजट में उच्च कूपन वाली अनकदी सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की एक योजना की घोषणा की है।

Loans taken from Financial Institutions

†*442. PROF. R. B. S. VARMA: Will the Minister of FINANCE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total amount of loan taken by Government from financial institutions alongwith the rate of interest payable on this loan;

(b) whether Government have formulated any scheme to repay the loan of these financial institutions; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH) : (a) Government issues securities to the market which are subscribed to by financial institutions. These securities have different implicit interest rates as they were issued at different periods of time.

(b) and (c) Government, in the budget 2003-04, have announced a scheme of buyback of high coupon illiquid Government securities.

†Original notice of the question was received in Hindi.

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा : माननीय सभापति ज़ी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मेरे सप्लीमेंटरी का ''अ'' भाग यह है कि वर्ष 2002-2003 के अंत तक बाजार में कुल कितनी धन राशि की प्रतिभूतियों का सरकार द्वारा निर्गम किया गया था और इस पर जो अंतर्निहित विभिन्न ब्याज दरें निर्धारित हैं, उस के अनुसार 2002-2003 के अंत तक सरकार पर मय ब्याज के कुल कितनी धन-राशि की देनदारी बनती है? इसी का ''ब'' भाग है कि वर्ष 2003-2004 के बजट में उच्च कूपन वाली अनकदी सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद योजना को कार्यान्वित करने और उसे मॉनीटर करने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है?

श्री जसवंत सिंह : माननीय सभापति जी, बहुत ही क्लिष्ट हिंदी में यह प्रश्न पूछा गया है।

श्री सभापति : आप क्लिष्ट अंग्रेजी में जवाब देते हैं, इसलिए उन्होंने क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया है।

श्री बालकवि बैरागी : मंत्री जी, आप तो राजस्थानी में जवाब दे दीजिए, वह राजस्थानी समझ लेंगे।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं भाषा का सरलीकरण करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री सभापति : बड़ी कृपा होगी।

श्री जसवंत सिंह : सभापति जी, कृपा तो आप की बनी रहे, तो बहुत अच्छा है।

सभापति जी, माननीय सदस्य के प्रश्न के भाग ''अ'' का सारांश है कि कुल राशि कितनी है? इस साल 2003-2004 की कुल राशि करीब 15 लाख 61 हजार करोड़ है और 2004-2005 में यह करीब 17 लाख 70 हजार करोड़ के करीब बन जाएगी। अगर रेशियो में देखना चाहें तो आज जो हमारी रेवेन्यू का अनुपात है, देश को जितनी आय है, उस आय का करीब 52 प्रतिशत ब्याज में चला जाता है और जी.डी.पी. के रेशियो में देखें तो जी.डी.पी. का करीब 60 प्रतिशत है जो कि बहुत ज्यादा है। महोदय, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बिल में इसे 10 साल में जी.डी.पी. के 50 प्रतिशत में लाने का प्रयत्न है। दूसरे, आप ने पूछा है कि राज्यों के जो ऋण है...

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा : मान्यवर, मैंने कहा कि उच्च कूपन वाली सरकारी अनकदी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद योजना जो आप ने बजट में घोषित की है...

श्री जसवंत सिंह : मैं समझ गया, यह बैंक्स से जुड़ा हुआ सवाल है और इसके दो-तीन पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। महोदय, हम बैंकों को बाध्य नहीं कर रहे हैं। यह वालंटियरी स्कीम है, खुली स्कीम होगी और अगर बैंक्स इसका लाभ उठाना चाहें तो करीब 44 हजार करोड़ रुपया, इस के प्रति जो मंहगी दर पर है, उस के स्थान पर सस्ती दर जो कि आज की दर है, उस दर पर यह हो जाएगा जिस से कि बैंकों को बहुत लाभ है, ऐसा हमारा विश्वास है।

प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा : माननीय सभापति जी, हमारी दूसरी सप्लीमेंटरी यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इस वर्ष के अंत तक लगभग 17,80,000 करोड़ रुपए की कुल देनदारी बनेगी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी देनदारी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनकी देनदारी भारत सरकार पर कितनी बनती है और उसे चुकाने के लिए क्या भारत सरकार कोई विशेष प्रयत्न कर रही है?

श्री जसवंत सिंह : सभापति जी, यह अंतर्राष्ट्रीय से आपका अर्थ है एक्सटर्नल डेब्ट से, तो एक्सटर्नल डेब्ट का जैसा सम्माननीय सदस्य को मालूम है, पहली बार सरकार की ओर से करीब तीन बिलियन डॉलर समय से पहले दे दिया जा चुका है और वह तीन बिलियन डॉलर लौटाने के बावजूद भी जो अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वे पुन: 75 मिलियन पर चले गए हैं। हमारा विश्वास है कि हम इसका समाधान इसी रास्ते से निकाल पाएंगे।

SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN : Sir, the hon. Finance Minister has, in his Budget, announced various schemes for buyback of high coupon securities. It is obvious, if high interest-yielding securities are returned, both to the States and others, then the interest income of the Central Government will go down. Would the hon. Minister inform the House what is the quantum of the interest loss to the Central Government as a result of these schemes and whether that has been factored in the Budget calculations?

SHRI JASWANT SINGH : Yes, Sir, because the interest loss is a notional loss at the moment; it has been factored in. What we are doing is to retire the high cost coupons on the voluntary basis, and to finance that retirement, we offer securities at the current rate. It is of interest to know, Sir, that the weighted average rate of securities in the 70's was roughly between 5 and 6 per cent. It went up to about 14 per cent in the 90's — during the period 1995-96. That has again begun to come down and we have now the weighted average of roughly about 10 per cent and, in the current year, of about 7 per cent. Now, you have asked whether we have factored in the aspect of interest loss. Yes, of course, because when you consider that the total interest liability upon the Government amounts to about 52 per cent of the revenue, then there is definitely an advantage in this scheme.

SHRI BACHANI LEKHRAJ : Sir, I would like to know whether the Goverrnment has ever considered the repayment of foreign loans from the amount that is colleted from disinvestment.

SHRI JASWANT SINGH : Sir, if I have understood the question correctly, the hon. Member is enquiring whether, from the disinvestment

proceeds, the Government has considered repayment of foreign loans. No, that is not one of the factors that drives the disinvestment policy.

MR. CHAIRMAN : Question No. 443.

Ban on discos in ITDC hotels

*443. SHRI VIJAY J. DARDA: Will the Minister of TOURISM AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have decided to ban discos at ITDC hotels and are advising private hotels also to close their discos and start promoting classical music and dances on the plea that discos are against Indian culture and are exerting bad influence on Bharatiya Sanskriti; and

(b) if so, whether its impact on foreign tourists has been taken into consideration?

THE MINISTER OF TOURISM AND CULTURE (SHRI JAGMOHAN) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) All hotels in India including ITDC and disinvested/under disinvestment and private hotels have to function in accordance with the existing Laws of Land and ensure that the cultural performances and music and dance functions are conducted in such a manner that they do not infringe the provisions of law on the subject. No direction/advice has been issued to any hotels in this regard.

(b) Does not arise.

श्री विजय जे॰ दर्डा : आदरणीय सभापति जी, सम्माननीय राज्यमंत्री भावना बेन जी ने कहा है कि भारतीय संस्कृति तथा हमारी सभ्यता को बरकरार रखने के लिए आईटीडीसी के होटलों में तथा देश के सभी मेन होटलों, ताँज, ऑबेराय आदि में जो डिस्को चल रहे हैं उनको बंद करेंगे। क्या माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि कितने आईटीडीसी होटलों में नियमित रूप से हम अपनी क्लासिकल संस्कृति और भारतीय नृत्य को प्रोमोट कर रहे हैं? इसके साथ ही जो विदेशी टूर आपरेटर हैं या जो भारतीय टूर आपरेटर हैं, जिनके पास टूरिस्ट आते हैं, क्या उन लोगों ने ऐसी कोई बात कही है कि वे वहां पर यह देखना चाहेंगे?

श्री सभापति : क्या आप बता सकते हैं कि कितने होटलों में यह डिस्को डांस चल रहे हैं?

श्री विजय जे॰ दर्डा : सर, यही मेरा सवाल है।